| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 3.872| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 4, Issue 9, September 2017 |

संविधान और साम्प्रदायिकता : समसामयिक राजनीति

Dr. Ganpat Ram Suthar

Associate Professor, SBK Govt. PG College, Jaisalmer, Rajasthan, India

सार

सांप्रदायिकता एक विवादित अवधारणा है। कुछ विद्वान और पत्रकार इसे समाज में पहले से मौजूद निश्चित सांप्रदायिक श्रेणियों के रूप में परिभाषित करते हैं, और इसका उपयोग समूहों के बीच राजनीतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक संघर्षों को समझाने के लिए करते हैं। [1] अन्य लोग सांप्रदायिकता को सामाजिक प्रथाओं के एक समूह के रूप में देखते हैं जहां दैनिक जीवन सांप्रदायिक मानदंडों और नियमों के आधार पर आयोजित किया जाता है जिन्हें व्यक्ति रणनीतिक रूप से उपयोग करते हैं और पार करते हैं। [2] [3] यह परिभाषा संप्रदायवाद को निश्चित और असंगत सांप्रदायिक सीमाओं के रूप में समझने के विपरीत, संप्रदायवाद और लोगों की एजेंसी के सह-संवैधानिक पहलू पर प्रकाश डालती है। [1] [2] [3]

जबकि संप्रदायवाद को अक्सर 'धार्मिक' और/या 'राजनीतिक' के रूप में लेबल किया जाता है, सांप्रदायिक स्थिति की वास्तविकता आमतौर पर बहुत अधिक जटिल होती है। अपने सबसे बुनियादी रूप में, सांप्रदायिकता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, 'एक इलाके के भीतर, दो या दो से अधिक विभाजित और सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिक पहचानों का अस्तित्व, जिसके परिणामस्वरूप द्वैतवाद की एक मजबूत भावना पैदा होती है, जो निरंतर समानता से परे है, और सांस्कृतिक और शारीरिक रूप से प्रकट होती है। . भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन (26 नवम्बर) भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है |जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।[1][2] [3] [4][5] भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम १९३५(1935) को माना जाता है।[6] भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतान्त्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है।

परिचय

ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में "सांप्रदायिकता" शब्द को "किसी विशेष संप्रदाय या पार्टी, विशेष रूप से धर्म में अत्यधिक लगाव" के रूप में परिभाषित किया गया है। [5] वाक्यांश " सांप्रदायिक संघर्ष " आमतौर पर धार्मिक या राजनीतिक आधार पर हिंसक संघर्ष को संदर्भित करता है, जैसे उत्तरी आयरलैंड में राष्ट्रवादियों और संघवादियों के बीच संघर्ष (धार्मिक और वर्ग-विभाजन भी प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं)। यह विभिन्न विचारधाराओं के बीच सामान्य दार्शनिक, राजनीतिक असमानता का भी उल्लेख कर सकता है, जैसे कि शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच । गैर-सांप्रदायिक लोग विभिन्न मान्यताओं के मुक्त सहयोग और सहिष्णुता को सफल, शांतिपूर्ण मानवीय संपर्क की आधारशिला के रूप में देखते हैं। वे राजनीतिक और धार्मिक बहुलवाद को अपनाते हैं ।[1,2]

"संप्रदायवाद" शब्द के विरुद्ध विवाद

कुछ विद्वान लेखों में "सांप्रदायिकता" शब्द का उपयोग करने में आने वाली समस्याओं की पहचान करते हैं। [6] [7] पश्चिमी मुख्यधारा के मीडिया और राजनेता अक्सर "सांप्रदायिकता" को प्राचीन और लंबे समय तक चलने वाला मानते हैं। उदाहरण के लिए, ओबामा ने अपने अंतिम स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में मध्य पूर्व में सांप्रदायिक हिंसा को "सहस्राब्दी पुराने संघर्षों में निहित" बताया, लेकिन कई लोगों ने बताया कि कुछ सांप्रदायिक तनाव एक दशक से भी पहले के नहीं हैं। [8] "संप्रदायवाद" भी बहुत अस्पष्ट है, जो इसे एक नारा बनाता है जिसका अर्थ पर्यवेक्षकों पर निर्भर है। [7] विद्वानों ने तर्क दिया कि "सांप्रदायिकता" शब्द का उपयोग संघर्षों के लिए एक आकर्षक व्याख्या बन गया है, जो विश्लेषणात्मक ध्यान को अंतर्निहित राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से दूर ले जाता है, सुसंगतता का अभाव है, और अक्सर भावनात्मक नकारात्मकता से जुड़ा होता है। [6] [7] कई विद्वानों को "सांप्रदायिकता" शब्द समस्याग्रस्त लगता है, और इसलिए तीन विकल्प प्रस्तावित हैं।

वैकल्पिक: संप्रदायीकरण

हाशमी और पोस्टेल और अन्य विद्वान "सांप्रदायिकता" और "सांप्रदायिकीकरण" के बीच अंतर करते हैं। [6] जबकि "संप्रदायवाद" एक समूह के भीतर उपविभाजनों के बीच विरोध, पूर्वाग्रह और भेदभाव का वर्णन करता है, उदाहरण के लिए उनकी धार्मिक या जातीय पहचान के आधार पर, उत्तरार्द्ध अपने राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए सत्तावादी संदर्भों के भीतर काम करने वाले राजनीतिक अभिनेताओं द्वारा जुटाई गई प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसमें लोकप्रिय शामिल हैं धार्मिक या पहचान चिह्नकों के

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 3.872| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 4, Issue 9, September 2017 |

आसपास लामबंदी। [6] मध्य पूर्व में सांप्रदायिक हिंसा और उसके उभार को समझाने के लिए संप्रदायवाद शब्द का उपयोग अपर्याप्त है, क्योंकि यह जटिल राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखता है। [6] अतीत और वर्तमान में, राजनीतिक लाभ और शक्ति की खोज में मध्य पूर्व के अंदर और बाहर राज्य अभिनेताओं द्वारा धार्मिक पहचान का राजनीतिकरण और लामबंदी की गई है । संप्रदायीकरण शब्द इस धारणा की संकल्पना करता है । [9] संप्रदायीकरण एक सक्रिय, बहुस्तरीय प्रक्रिया और प्रथाओं का एक सेट है, न कि एक स्थिर स्थिति, जो राजनीतिक लक्ष्यों का पीछा करने वाले राजनीतिक अभिनेताओं द्वारा गति और आकार में निर्धारित की जाती है। [9] [10] [11] संप्रदायीकरण थीसिस ऊपर से नीचे राज्य-केंद्रित परिप्रेक्ष्य से राजनीति और सांप्रदायिक पहचान के प्रतिच्छेदन पर केंद्रित है। [6] जबकि धार्मिक पहचान मध्य पूर्व में प्रमुख है और इसने पूरे क्षेत्र में संघर्षों में योगदान दिया है और इसे तीव्र किया है, यह कुछ पहचान चिह्नों ("संप्रदायीकरण") के आसपास लोकप्रिय भावनाओं का राजनीतिकरण और लामबंदी है जो सांप्रदायिक हिंसा की सीमा और वृद्धि को स्पष्ट करता है। मध्य पूर्व में। [9] मध्य पूर्व में संप्रदायीकरण की प्रक्रिया में ओटोमन तंज़ीमत , यूरोपीय उपनिवेशवाद और अधिनायकवाद प्रमुख हैं।

वैकल्पिक: उपसर्ग के रूप में सांप्रदायिक

हद्दाद का तर्क है कि "सांप्रदायिकता" वास्तविकता में सांप्रदायिक संबंधों पर कब्जा नहीं कर सकती है और न ही सांप्रदायिक पहचान की जटिल अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। [7] हद्दाद ने विद्वानों के शोध में "सांप्रदायिकता" को त्यागने का आह्वान किया है क्योंकि इसने "जड़ को खत्म कर दिया है" और "सांप्रदायिक पहचान को समझने की दिशा में हमारे विश्लेषणात्मक ध्यान को निर्देशित करने" के लिए एक योग्यता के रूप में 'सांप्रदायिक' का प्रत्यक्ष उपयोग किया है । [7] सांप्रदायिक पहचान "एक साथ चार अतिव्यापी, परस्पर जुड़े हुए और पारस्परिक रूप से सूचित करने वाले आयामों के साथ तैयार की गई है: सैद्धांतिक, उपराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय"। [7] इन कारकों की प्रासंगिकता संदर्भ पर निर्भर है और कोरस में चार परतों पर काम करती है। बहुस्तरीय कार्य अधिक स्पष्टता प्रदान करता है और अधिक विशिष्ट समाधान खोजने के लिए कुछ आयामों पर समस्याओं का अधिक सटीक निदान करने में सक्षम बनाता है।[2,3]

वैकल्पिक: लिंगभेदवाद

अपनी पुस्तक सेक्स्टेरियनिज़्म में, मिकदाशी संप्रदाय, लिंग और कामुकता के बीच संबंधों पर जोर देती है। उनका तर्क है कि संप्रदायवाद का अध्ययन अलगाव में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संप्रदायवाद का अभ्यास हमेशा लिंगवाद के अभ्यास के साथ-साथ चलता है । इस कारण से वह "सेक्सटेरियनिज़्म" शब्द का प्रस्ताव करती है। लिंग, कामुकता और संप्रदाय मिलकर नागरिकता को परिभाषित करते हैं, और, चूंकि नागरिकता की अवधारणा आधुनिक राष्ट्र-राज्य का आधार है, इसलिए लिंगभेदवाद राज्य की कानूनी नौकरशाही प्रणालियों और इस प्रकार राज्य सत्ता के लिए आधार बनता है। [14]

सांप्रदायिकता में अंतर्विभागीयता

संप्रदायवाद की जांच में अंतर्विरोध की विश्लेषणात्मक रूपरेखा ने इस विषय के अध्ययन में बढ़ती प्रमुखता प्राप्त की है। अंतर्विभागीयता सांप्रदायिक तनावों और संघर्षों द्वारा चिह्नित संदर्भों में धार्मिक, जातीय, राजनीतिक और सामाजिक पहचान की प्रकृति पर प्रकाश डालती है। [15] यह स्वीकार करना कि संप्रदायवाद के व्यक्तियों के अनुभव न केवल उनकी धार्मिक संबद्धता या अन्य सांप्रदायिक श्रेणियों से आकार लेते हैं, बल्कि लिंग, वर्ग और राष्ट्रीयता जैसे अन्य आयामों से भी प्रभावित होते हैं, अनिवार्य रूप से उन अनुभवों में योगदान दे रहे हैं। [16]

धार्मिक आयाम

अंतर्विभागीयता से पता चलता है कि लिंग, जातीयता और सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कारक व्यक्तियों के सांप्रदायिकता के अनुभवों को आकार देने के लिए धार्मिक पहचान के साथ प्रतिच्छेद करते हैं। माया मिकदाशी जैसे लेखकों ने 'सेक्सटेरियनिज्म' की अवधारणा पेश की, विशेष रूप से यह दिखाया कि कैसे लिंग की भूमिका लेबनान जैसे राजनीतिक सांप्रदायिक प्रणालियों में धार्मिक सांप्रदायिक मतभेदों के व्यक्ति के अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रही है। [14] लेबनान में सांप्रदायिकता के मामले में , वह इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे एक राजनीतिक सांप्रदायिक व्यवस्था में महिलाओं की शक्ति और संप्रभुता के अनुभवों को निर्धारित करने में सेक्स्टेरियन मतभेद निर्णायक कारक हैं।

राजनीतिक आयाम

राजनीतिक आयामों में, अंतर्विरोध लेंस राजनीतिक पहचान और अन्य सामाजिक श्रेणियों के बीच जटिल संबंधों को पहचानता है। राजनीतिक दल या अन्य गुट राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक विभाजन का फायदा उठा सकते हैं, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। [17] अंतर्विभागीयता यह समझने में मदद करती है कि उदाहरण के लिए राजनीतिक संबद्धताएं सामाजिक-आर्थिक स्थिति और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि जैसे कारकों के साथ कैसे जुड़ती हैं, जो राजनीतिक लामबंदी के पीछे की प्रेरणा और सांप्रदायिक सेटिंग्स में शक्ति की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। [18]

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 3.872| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 4, Issue 9, September 2017 |

समुदायों के लिए निहितार्थ

सांप्रदायिकता की अंतर्विरोधता का प्रभावित समुदायों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जो कई हाशिए वाले समूहों से संबंधित हैं जैसे कि महिलाएं, प्रवासी और सांप्रदायिक प्रणालियों के तहत रहने वाली हाशिए पर रहने वाली जातीयताएं। विभिन्न समाजों के भीतर शांति, सहिष्णुता और बढ़ी हुई सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए समावेशी रणनीति विकसित करने के लिए भेदभाव और हाशिए के इन परस्पर रूपों की पहचान निर्णायक है।[3,4]

राजनीतिक संप्रदायवाद

21वीं सदी में संप्रदायवाद

राजनीति में सांप्रदायिक प्रवृत्तियाँ वर्तमान और अतीत में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े देशों और शहरों में दिखाई देती हैं। [19] उल्लेखनीय उदाहरण जहां सांप्रदायिकता जीवन को प्रभावित करती है, वे हैं सड़क-कला अभिव्यक्ति, शहरी नियोजन और खेल क्लब संबद्धता। [20]

यूनाइटेड किंगडम

पूरे यूनाइटेड किंगडम में, स्कॉटिश और आयरिश सांप्रदायिक प्रवृत्तियाँ अक्सर टीम-खेल प्रतियोगिताओं में परिलक्षित होती हैं। [21] संबद्धता को संप्रदायवाद की प्रवृत्ति का एक गुप्त प्रतिनिधित्व माना जाता है। (1900 के दशक की शुरुआत से, क्रिकेट टीमों की स्थापना सांप्रदायिक संबद्ध जमींदारों के संरक्षण के माध्यम से की गई थी। खेल के प्रोटेस्टेंट प्रतिनिधित्व के जवाब में, कई कैथोलिक स्कूलों ने अपने स्वयं के क्रिकेट स्कूलों की स्थापना की। [[22] [20]) आधुनिक समय के उदाहरणों में खेल में तनाव शामिल है जैसे कि फुटबॉल और इसके कारण "फुटबॉल में आक्रामक व्यवहार और धमकी भरे संचार (स्कॉटलैंड) अधिनियम 2012 " पारित हुआ। [23] [24] अन्य सामान्य उदाहरणों में आयरलैंड में गेलिक खेल शामिल हैं, जो आयरिश पहचान को संरक्षित करने के लिए ब्रिटिश पारंपरिक खेलों के प्रतिकार के रूप में स्थापित किए गए थे। [25]

ईरान

विश्व नेताओं ने ईरान की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की आलोचना की है और हिजबुल्लाह जैसे विपक्षी समूहों के लिए इसकी भागीदारी और समर्थन की निंदा की है । [26] इस्लामी गणतंत्र ईरान का राजनीतिक अधिकार पड़ोसी देशों तक फैल गया है, और इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। [27]

विस्तार की इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ईरान की कुद्स फोर्स (आईआरजीसी की विदेशी शाखा) के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी थे । [28] जनवरी 2016 में एक अमेरिकी ड्रोन द्वारा इराक में सुलेमानी की हत्या कर दी गई, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया। [29] सुलेमानी लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया के अल-असद और इराक में शिया मिलिशिया समूहों जैसी विदेशी शक्तियों के साथ ईरान के संबंधों को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार थे। [29] सुलेमानी को ईरान की विदेशी सेनाओं के नंबर एक कमांडर के रूप में देखा जाता था और उन्होंने क्षेत्र में ईरान की विचारधारा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अनुसार , सुलेमानी दुनिया का सबसे वांछित आतंकवादी था और मध्य-पूर्व क्षेत्र और बाकी दुनिया में अधिक शांति लाने के लिए उसकी हत्या की जानी थी। [30] हालाँकि यह गलत साबित हुआ क्योंकि उनकी हत्या का ईरानी महत्वाकांक्षाओं पर बहुत कम प्रभाव पड़ा और केवल ईरान के लिए समर्थन बढ़ा क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक अवैध कार्य था।[4,5]

सत्तावादी शासन

हाल के वर्षों में, अधिनायकवादी शासन विशेष रूप से संप्रदायीकरण की ओर प्रवृत्त हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अस्तित्व की मुख्य रणनीति परिवर्तन और न्याय की मांगों को भटकाने और अपनी शक्ति को संरक्षित और कायम रखने के लिए सांप्रदायिक पहचान में हेरफेर करने में निहित है। [9] एक सिद्धांत और प्रक्रिया के रूप में संप्रदायीकरण जो मध्य पूर्व से आगे तक फैला था, सलीना सलीम द्वारा पेश किया गया था (देखें [31] और [32])। मध्य पूर्व में ईसाई समुदायों और अन्य धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को मुख्य रूप से उन शासनों द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहिष्कृत और नुकसान पहुंचाया गया है जो " अरब राष्ट्रवाद और/या इस्लाम की अपील करके सत्ता हासिल करने और अपने आधार में हेरफेर करने " पर ध्यान केंद्रित करते हैं। [33] इसका एक उदाहरण 1979 की ईरानी क्रांति के प्रति मध्य पूर्वी क्षेत्रीय प्रतिक्रिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका , विशेष रूप से सऊदी अरब द्वारा समर्थित मध्य पूर्वी तानाशाही को डर था कि क्रांतिकारी भावना और विचारधारा के प्रसार से उनकी शक्ति और प्रभुत्व प्रभावित होगा। क्षेत्र। इसलिए, इसे सुन्नी इस्लामी परंपरा को भ्रष्ट करने की शिया साजिश का नाम देकर ईरानी क्रांति को कमजोर करने का प्रयास किया गया । इसके बाद पूरे क्षेत्र में शिया-विरोधी भावनाओं में वृद्धि हुई और खाड़ी देशों के धन से प्रेरित होकर शिया-सुन्नी संबंधों में गिरावट आई । [9] इसलिए, संप्रदायीकरण की प्रक्रिया, सांप्रदायिक पहचानों की लामबंदी और राजनीतिकरण, सत्तावादी शासन के लिए अपनी शक्ति को बनाए रखने और हिंसा को उचित ठहराने का एक राजनीतिक उपकरण है। [9] पश्चिमी शक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से मध्य पूर्व में अलोकतांत्रिक शासन का समर्थन करके संप्रदायीकरण की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। [11] जैसा कि नादेर हाशमी दावा करते हैं:

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 3.872| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 4, Issue 9, September 2017 |

इराक पर अमेरिकी आक्रमण; सऊदी अरब साम्राज्य के लिए विभिन्न पश्चिमी सरकारों का समर्थन, जो यमन में युद्ध अपराध पर युद्ध अपराध करता है और पूरे सुन्नी दुनिया में जहरीला सांप्रदायिक प्रचार फैलाता है; अत्यधिक दमनकारी तानाशाहों के लिए लंबे समय से पश्चिमी समर्थन का उल्लेख नहीं किया गया है, जो नियंत्रण और शासन के अस्तित्व की रणनीति के रूप में सांप्रदायिक भय और चिंताओं में हेरफेर करते हैं - "प्राचीन नफरत" कथा [सुन्नियों और शियाओं के बीच] इस सब को दूर कर देती है और क्षेत्र के लोगों को दोष देती है कथित ट्रांस-ऐतिहासिक धार्मिक भावनाओं पर समस्याएं। यह चरम सीमा पर बेतुका है और बुरे विश्वास का अभ्यास है। [11]

सत्तावादी शासन में सांप्रदायिक पहचान का अध्ययन करने के दृष्टिकोण [5,6]

विद्वानों ने सांप्रदायिक प्रवचनों का अध्ययन करने के लिए तीन दृष्टिकोण अपनाए हैं: आदिमवाद , यंत्रवाद , और रचनावाद । [5] [9] [34] आदिमवाद सांप्रदायिक पहचान को जीव विज्ञान में सड़ चुकी और इतिहास और संस्कृति में समाहित मानता है। [5] मकदिसी ने सांप्रदायिक प्रवचनों को प्रारंभिक इस्लामी इतिहास में वापस लाने की प्रक्रिया को "व्यापक मध्ययुगीनकरण" के रूप में वर्णित किया है। [35] सदियों पुरानी कथा समस्याग्रस्त है क्योंकि यह मध्य पूर्व में सांप्रदायिक पहचान को आधुनिक सामूहिक पहचान के बजाय सुई जेनरिस के रूप में मानती है। [7] विद्वानों को सांप्रदायिक अनिवार्यता और मध्य पूर्व असाधारणता से सावधान रहना चाहिए, आदिम कथा इसे पुष्ट करती है क्योंकि आदिमवाद सुझाव देता है कि सांप्रदायिक तनाव बना रहता है जबकि धार्मिक मतभेद संघर्ष की गारंटी नहीं देते हैं। [7] [9] [35] वाद्यवाद इस बात पर जोर देता है कि सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग अपने हितों के लिए हिंसक संघर्ष पैदा करने के लिए पहचान में हेरफेर करता है। वाद्ययंत्रवादी सुन्नी-शिया विभाजन को एक आधुनिक आविष्कार के रूप में देखते हैं और आदिम कथाओं के मिथकों को चुनौती देते हैं क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव सदियों से मौजूद है। [5] रचनावाद आदिमवाद और यंत्रवाद के बीच में है।

धार्मिक संप्रदायवाद

जहां भी विभिन्न धर्मों के लोग एक-दूसरे के करीब रहते हैं, वहां धार्मिक संप्रदायवाद अक्सर अलग-अलग रूपों और डिग्री में पाया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में, धार्मिक संप्रदायवादी (उदाहरण के लिए प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ईसाई) अब अधिकांश भाग में शांतिपूर्वक साथ-साथ रहते हैं, हालांकि इन मतभेदों के परिणामस्वरूप हाल ही में 1990 के दशक में हिंसा, मृत्यु और पूर्ण युद्ध हुआ है। संभवतः हाल के दिनों में सबसे प्रसिद्ध उदाहरण द ट्रबल्स थे ।

कैथोलिक-प्रोटेस्टेंट संप्रदायवाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति अभियानों में एक कारक रहा है। जॉन एफ. कैनेडी से पहले , केवल एक कैथोलिक (अल स्मिथ) ही प्रमुख पार्टी का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार था, और अपने कैथोलिक धर्म पर आधारित दावों के कारण वह बड़े पैमाने पर बुरी तरह हार गया था। जेएफके ने वेस्ट वर्जीनिया प्राइमरी के दौरान सांप्रदायिक मुद्दे से सीधे तौर पर निपटने का फैसला किया, लेकिन यह उन्हें बमुश्किल पर्याप्त प्रोटेस्टेंट वोट दिलाने के लिए पर्याप्त था, जो अंततः अब तक के सबसे कम अंतर से राष्ट्रपति पद जीतने के लिए पर्याप्त था। [36]

इस्लाम के भीतर , सुन्नियों और शियाओं के बीच विभिन्न अवधियों में दुविधाएं रही हैं ; शिया सुन्नियों को झूठा मानते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ख़लीफ़ा को अली के रूप में स्वीकार करने से इंकार कर दिया था और उसके बाद के सभी वंशजों को अचूक और दैवीय रूप से निर्देशित मानने से इनकार कर दिया था। कई सुन्नी धार्मिक नेताओं, जिनमें वहाबीवाद और अन्य विचारधाराओं से प्रेरित लोग भी शामिल हैं, ने शियाओं को विधर्मी या धर्मत्यागी घोषित कर दिया है । [37]

यूरोप

सुधार से बहुत पहले, 12वीं शताब्दी में, आयरलैंड में अलग-अलग तीव्रता का सांप्रदायिक संघर्ष रहा है। ऐतिहासिक रूप से, कुछ कैथोलिक देशों ने एक बार प्रोटेस्टेंटों को विधर्मी के रूप में सताया था। उदाहरण के लिए, फ्रांस की बड़ी प्रोटेस्टेंट आबादी (ह्यूजेनॉट्स) को 1680 के दशक में नैनटेस के आदेश के रद्द होने के बाद राज्य से निष्कासित कर दिया गया था । स्पेन में, इनक्विज़िशन ने क्रिप्टो-यहूदियों और क्रिप्टो-मुसलमानों (मॉरिस्कोस) को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की ; अन्यत्र भी पोप धर्माधिकरण के समान लक्ष्य थे।[6,7]

कुछ देशों में जहां सुधार सफल रहा, वहां रोमन कैथोलिकों का उत्पीड़न हुआ। यह इस धारणा से प्रेरित था कि कैथोलिकों ने एक 'विदेशी' शक्ति (पोपेसी या वेटिकन) के प्रति निष्ठा बरकरार रखी, जिससे उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। कभी-कभी यह अविश्वास कैथोलिकों द्वारा प्रतिबंधों और भेदभाव के अधीन होने में प्रकट होता था, जिसके कारण आगे चलकर संघर्ष होता था। उदाहरण के लिए, रोमन कैथोलिक राहत अधिनियम 1829 के साथ कैथोलिक मुक्ति लागू होने से पहले , कैथोलिकों को मतदान करने, सांसद बनने या आयरलैंड में जमीन खरीदने से मना किया गया था।

आयरलैंड

आयरिश इतिहास में प्रोटेस्टेंट-कैथोलिक संप्रदायवाद प्रमुख है ; अंग्रेजी (और बाद में ब्रिटिश) शासन की अवधि के दौरान , ब्रिटेन से प्रोटेस्टेंट निवासियों को आयरलैंड में "रोपित" किया गया, जिसके कारण प्रोटेस्टेंट सुधार के साथ-साथ आयरिश कैथोलिक और

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 3.872| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 4, Issue 9, September 2017 |

ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। ये तनाव अंततः 1641 के आयरिश विद्रोह के दौरान व्यापक हिंसा में बदल गया । उस युद्ध के अंत में आयरलैंड के निपटान अधिनियम 1652 के तहत नए अंग्रेजी मालिकों को दी गई दस मिलियन एकड़ से अधिक भूमि के साथ कैथोलिकों की भूमि जब्त कर ली गई थी । [38] आयरलैंड की क्रॉमवेलियन विजय (1649-1653) में कैथोलिक अंग्रेजी राजभक्तों और आयरिश नागरिकों के खिलाफ प्रोटेस्टेंट न्यू मॉडल आर्मी द्वारा किए गए नरसंहारों की एक श्रृंखला देखी गई। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच सांप्रदायिकता आयरलैंड साम्राज्य में जारी रही , ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1798 के आयरिश विद्रोह के कारण द्वीप में अधिक सांप्रदायिक हिंसा हुई, सबसे कुख्यात स्कलबोग बार्न नरसंहार , जिसमें प्रोटेस्टेंट को काउंटी वेक्सफ़ोर्ड में जिंदा जला दिया गया था । [39] विद्रोह पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया जिसमें डनलविन और कार्न्यू में दर्जनों संदिग्ध विद्रोहियों की सार्वजनिक फांसी शामिल थी , ने भी सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया।

उत्तरी आयरलैंड

1922 में आयरलैंड के विभाजन के बाद , उत्तरी आयरलैंड ने प्रमुख प्रोटेस्टेंट बहुमत और कैथोलिक अल्पसंख्यक के बीच दशकों तक तीव्र संघर्ष, तनाव और छिटपुट हिंसा देखी (देखें द ट्रबल्स (1920-1922) और द ट्रबल्स)। 1969 में उत्तरी आयरलैंड नागरिक अधिकार संघ का गठन नागरिक अधिकारों का समर्थन करने और मतदान के अधिकार (देखें गेरीमांडरिंग), आवास आवंटन और रोजगार में भेदभाव (धर्म के आधार पर) को समाप्त करने के लिए किया गया था। इसके अलावा 1969 में, 25 वर्षों की हिंसा भड़क उठी, जिसे आयरिश रिपब्लिकन, जिनका लक्ष्य संयुक्त आयरलैंड है और अल्स्टर के वफादारों, जो उत्तरी आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, के बीच "मुसीबतों" के रूप में जाना जाता है। यह संघर्ष मुख्य रूप से धर्म के बजाय उत्तरी आयरिश राज्य के अस्तित्व को लेकर लड़ा गया था, हालाँकि उत्तरी आयरलैंड के भीतर सांप्रदायिक संबंधों ने संघर्ष को बढ़ावा दिया। हालाँकि, धर्म का उपयोग आमतौर पर समुदाय के दोनों पक्षों को अलग करने के लिए एक मार्कर के रूप में किया जाता है। कैथोलिक अल्पसंख्यक मुख्य रूप से राष्ट्रवादी और कुछ हद तक रिपब्लिकन, आयरलैंड गणराज्य के साथ एकता के लक्ष्य का समर्थन करते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट बहुमत उत्तरी आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन के साथ जारी रखने का समर्थन करते हैं।

इंग्लैंड

जून 1780 में कैथोलिक विरोधी भावना से प्रेरित होकर लंदन में दंगों की एक श्रृंखला (देखें गॉर्डन दंगे) हुई । इन दंगों को लंदन के इतिहास में सबसे विनाशकारी बताया गया और इसके परिणामस्वरूप लगभग 300-700 मौतें हुईं। [40] आयरलैंड में राजनीतिक और धार्मिक रूप से प्रेरित सांप्रदायिक हिंसा का एक लंबा इतिहास पहले से ही मौजूद था (आयरिश विद्रोह देखें)। " आयरिश प्रश्न " से संबंधित सांप्रदायिक विभाजन ने इंग्लैंड में स्थानीय घटक राजनीति को प्रभावित किया।

लिवरपूल एक अंग्रेजी शहर है जो कभी-कभी सांप्रदायिक राजनीति से जुड़ा होता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में, लिवरपूल को आयरलैंड में महान अकाल के परिणामस्वरूप आयरिश कैथोलिकों के बड़े पैमाने पर आप्रवासन का सामना करना पड़ा । अधिकांश आयरिश-कैथोलिक आप्रवासी अकुशल श्रमिक थे और उन्होंने खुद को लेबर पार्टी के साथ जोड़ लिया। [41] [42] लेबर-कैथोलिक पार्टी ने कई लिवरपूल-आयरिश में एक बड़ा राजनीतिक मतदाता देखा, और आयरिश मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए अक्सर "होम रूल" - आयरलैंड की स्वतंत्रता के नारे पर चलती थी। 20वीं सदी की पहली छमाही के दौरान, लिवरपूल की राजनीति न केवल कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच विभाजित थी, बल्कि कई पहचान वाले दो ध्रुवीकृत समूहों के बीच भी विभाजित थी: कैथोलिक-लिबरल-लेबर और प्रोटेस्टेंट-कंजर्वेटिव-टोरी/ऑरेंजिस्ट। [43] [44]

1900 की शुरुआत से, ध्रुवीकृत कैथोलिक लेबर और प्रोटेस्टेंट कंजर्वेटिव संबद्धताएं धीरे-धीरे टूट गईं और मिश्रित गठबंधनों के लिए अवसर पैदा हुआ। आयरिश नेशनल पार्टी ने 1875 में अपनी पहली चुनावी जीत हासिल की, और 1921 में आयरिश स्वतंत्रता की प्राप्ति तक बढ़ती रही, जिसके बाद यह श्रम समर्थन पर कम निर्भर हो गई। प्रोटेस्टेंट पक्ष में, 1902 में प्रोटेस्टेंट प्रस्तावित बिलों के अनुरूप मतदान करने के लिए टोरी के विरोध ने श्रमिक वर्ग प्रोटेस्टेंट और टोरी पार्टी के बीच विभाजन का संकेत दिया, जिन्हें इसके मतदाताओं से "बहुत दूर" माना जाता था। [44] [45]

प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, धार्मिक रूप से मिश्रित बटालियनों ने दोनों ओर से रोमन कैथोलिक विरोधी और प्रोटेस्टेंट विरोधी प्रचार का जवाब दिया। [46] जबकि 1939 में आईआरए-बमबारी (एस-प्लान देखें) ने आयरिश-कैथोलिक संबद्ध लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव प्रोटेस्टेंट के बीच हिंसा को कुछ हद तक बढ़ा दिया, जर्मन मे ब्लिट्ज ने 40,000 से अधिक घरों की संपत्ति को नष्ट कर दिया। [44] युद्ध के बाद लिवरपूल के पुनर्निर्माण ने धार्मिक आधार पर समुदाय की एक नई भावना पैदा की। [47] एक प्रतिक्रिया के रूप में अंतर-चर्च संबंधों में भी वृद्धि हुई, जैसा कि 1976 के बाद आर्कबिशप वर्लॉक और एंग्लिकन बिशप डेविड शेपर्ड के बीच संबंधों की गर्माहट के माध्यम से देखा गया , जो कम होती धार्मिक शत्रुता का प्रतीक है। [48] शिक्षा दरों में वृद्धि और व्यापार और श्रमिक संघों के उदय ने धार्मिक संबद्धता को वर्ग संबद्धता में स्थानांतरित कर दिया, जिससे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक सहयोगियों को राजनीति में लेबर छत्रछाया के तहत अनुमति मिल गई। 1980 के दशक में, वर्ग विभाजन धार्मिक विभाजन से आगे निकल गया था और धार्मिक संप्रदायवाद की जगह वर्ग संघर्ष ने ले ली थी। [44] 21वीं सदी के आसपास राष्ट्रमंडल के अन्य हिस्सों से गैर-अंग्रेजी आप्रवासन की बढ़ती दर भी पहचान संबद्धता में विभाजन की नई राजनीतिक रेखाएं प्रदान करती है। [49]

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 3.872| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 4, Issue 9, September 2017 |

उत्तरी आयरलैंड ने 2007 से एक निजी चिंतन दिवस, [50] की शुरुआत की है, जो कि एक संघर्ष-पश्चात समाज में परिवर्तन को चिह्नित करने के लिए है, जो कि क्रॉस-कम्युनिटी हीलिंग थ्रू रिमेम्बरिंग [51] संगठन और अनुसंधान परियोजना की एक पहल है।[7,8]

बाल्कन

1990 के दशक में यूगोस्लाविया के विघटन के बाद बाल्कन में हुए गृह युद्धों में भारी सांप्रदायिकता का रंग था। क्रोएट्स और स्लोवेनिया पारंपरिक रूप से कैथोलिक, सर्ब और मैसेडोनियन पूर्वी रूढ़िवादी , और बोस्नियाक्स और अधिकांश अल्बानियाई मुस्लिम रहे हैं। साम्यवाद के दशकों के बाद इन विभिन्न समूहों के बीच धार्मिक अभ्यास और विश्वास की अपेक्षाकृत कम दर के बावजूद, धार्मिक संबद्धता ने इस संघर्ष में समूह की पहचान के एक मार्कर के रूप में कार्य किया ।

अफ्रीका

2013-2014 में मध्य अफ्रीकी गणराज्य में सांप्रदायिक हिंसा में 1,000 से अधिक मुस्लिम और ईसाई मारे गए । [52] लगभग 10 लाख लोग, यानी आबादी का एक चौथाई, विस्थापित हो गए। [53]

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया में संप्रदायवाद मुख्य रूप से सेल्टिक विरासत के कैथोलिकों और मुख्य रूप से अंग्रेजी मूल के प्रोटेस्टेंटों के बीच 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी की एक ऐतिहासिक विरासत है। 21वीं सदी में यह काफी हद तक गायब हो गया है। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की पृष्ठभूमि के बीच, धार्मिक तनाव मुस्लिम आप्रवासियों और गैर-मुस्लिम राष्ट्रवादियों के बीच अधिक केंद्रित थे

एशिया

जापान

जापान में बौद्ध संप्रदायों के बीच हिंसक संघर्ष के लिए, जापानी बौद्ध धर्म देखें ।

पाकिस्तान

दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देशों में से एक पाकिस्तान में गंभीर शिया - सुन्नी सांप्रदायिक हिंसा देखी गई है । [59] पाकिस्तान की लगभग 85-90% मुस्लिम आबादी सुन्नी है , और अन्य 10-15% शिया हैं । [60] [61] हालाँकि, यह शिया अल्पसंख्यक किसी भी देश की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी है, जो इराक में शिया बहुमत से भी बड़ी है ।

पिछले दो दशकों में, पाकिस्तान में सांप्रदायिक लड़ाई में लगभग 4,000 लोगों के मारे जाने का अनुमान है, 2006 में 300। [62] हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दोषियों में अल कायदा भी शामिल है जो "स्थानीय सांप्रदायिक समूहों के साथ" काम कर रहा है ताकि वे मारे जा सकें। शिया धर्मत्यागी के रूप में समझें। [62]

श्रीलंका

श्रीलंका में अधिकांश मुसलमान सुन्नी हैं। बोहरा के अपेक्षाकृत छोटे व्यापारिक समुदाय से कुछ शिया मुसलमान भी हैं। बेरुवाला के लिए विभाजन कोई नई बात नहीं है। कलुतारा जिले में सुन्नी मुसलमान दो अलग-अलग उप समूहों में विभाजित हैं। एक समूह, जिसे अलाविया संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, ऐतिहासिक रूप से बेरुवाला में मत्स्य पालन बंदरगाह से सटे ताड़ के किनारे स्थित केचिमलाई मस्जिद में अपना वार्षिक उत्सव आयोजित करता है।

यह कई मायनों में मुस्लिम पहचान का एक सूक्ष्म रूप है। गैले रोड जो कोलंबो से तट को छूती है, शहर के ठीक आगे अंदर की ओर घूमती है और विभाजन बनाती है। सड़क के बाईं ओर चीन का किला है, वह क्षेत्र जहां श्रीलंका के कुछ सबसे धनी मुसलमान रहते हैं। सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त महलनुमा घर कोलंबो 7 सेक्टर के घरों से आगे नहीं तो उनके बराबर भी हो सकते हैं। अधिकांश धनी मुसलमानों, रत्न व्यापारियों के पास राजधानी में घर भी है, संपत्ति का तो जिक्र ही नहीं।

कट्टर वहाबी मानते हैं कि जो लोग उनके धर्म का पालन नहीं करते, वे बुतपरस्त और दुश्मन हैं। कुछ अन्य लोग भी हैं जो तालिबान के साथ-साथ ओसामा बिन लादेन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि वहाबीवाद की कठोरता ने इसे इस्लाम की गलत व्याख्या और विकृत करने के लिए प्रेरित किया है। बेरुवाला में इस नई घटना की अभिव्यक्ति ने खुफिया और सुरक्षा हलकों में चिंता पैदा कर दी है। इससे पहले इसका उद्भव पूर्व में देखा गया था।[8,9]

टर्की

ऑटोमन साम्राज्य

1511 में, सहकुलु विद्रोह के नाम से जाना जाने वाला एक शिया समर्थक विद्रोह ओटोमन्स द्वारा बेरहमी से दबा दिया गया था: सुल्तान के आदेश पर 40,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। [63]

गणतांत्रिक युग (1923-)

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 3.872| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 4, Issue 9, September 2017 |

एलेविस को 1978 मारास नरसंहार , 1980 कोरम नरसंहार और 1993 सिवास नरसंहार सहित विभिन्न नरसंहारों में निशाना बनाया गया था ।

2016 के तुर्की राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने अभियान के दौरान , केमल किलिकडारोग्लु पर अदियामन में सांप्रदायिक अपमान के साथ हमला किया गया था । [64]

ईरान

ईरान में सांप्रदायिकता सदियों से अस्तित्व में है, जो शुरुआती इस्लामी वर्षों में देश पर इस्लामी विजय के समय से चली आ रही है और पूरे ईरानी इतिहास में वर्तमान तक जारी है। सफ़ाविद राजवंश के शासनकाल के दौरान , सांप्रदायिकता ने देश के मार्ग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। [65] 1501 और 1722 के बीच सफ़ाविद शासन के दौरान, शियावाद विकसित होना शुरू हुआ और आधिकारिक राज्य धर्म के रूप में स्थापित हो गया, जिससे बारहवें इमाम के शासनकाल के बाद पहली धार्मिक रूप से वैध सरकार का निर्माण हुआ । [66] संप्रदायवाद का यह पैटर्न पूरे ईरानी इतिहास में प्रचलित रहा। ईरानी 1979 की क्रांति के बाद संप्रदायवाद ने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह पहले की अवधि की तुलना में बदल गया है। 1979 की ईरानी क्रांति से पहले कभी भी शिया नेतृत्व को इतना अधिकार हासिल नहीं हुआ था। [67] इस परिवर्तन के कारण, ईरान में सांप्रदायिक समयरेखा को 1979 की ईरानी क्रांति से पहले और बाद में विभाजित किया जा सकता है जहां धार्मिक नेतृत्व ने अपना रास्ता बदल लिया।

1979 से पहले की क्रांति

1979 की ईरानी क्रांति से बहुत पहले से, ईरान के भीतर राजनीति, संस्कृति और धर्म को आकार देने में शियावाद एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। [65] सफ़ाविद राजवंश के दौरान शिया धर्म आधिकारिक विचारधारा के रूप में स्थापित हुआ। [65] एक आधिकारिक सरकारी विचारधारा के रूप में शियावाद की स्थापना ने पादरियों के लिए नए सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक अधिकारों से लाभ उठाने के द्वार खोल दिए, जिन्हें सफ़ाविद शासन से पहले अस्वीकार कर दिया गया था। [65] सफ़ाविद राजवंश के दौरान शिया धर्म आधिकारिक विचारधारा के रूप में स्थापित हुआ। [65] सफ़ाविद शासन ने धार्मिक नेताओं के लिए अधिक स्वतंत्रता की अनुमति दी। शिया धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्थापित करके, उन्होंने धार्मिक अधिकार को वैध बना दिया। इस सत्ता स्थापना के बाद, धार्मिक नेताओं ने राजनीतिक व्यवस्था के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहे। [68] सफ़ाविद काल के दौरान राजशाही शक्ति संतुलन हर कुछ वर्षों में बदल जाता था, जिसके परिणामस्वरूप पादरी की शक्ति की सीमा बदल जाती थी। धार्मिक अधिकारियों और शासक शक्ति के बीच शक्ति संबंधों से संबंधित तनाव ने अंततः 1906 की संवैधानिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसने सम्राट की शक्ति को सीमित कर दिया और धार्मिक नेताओं की शक्ति में वृद्धि की। [69] 1906 की संवैधानिक क्रांति में संविधानवादी और संविधान-विरोधी दोनों पादरी नेता शामिल थे। सैय्यद जमाल अल-दीन वैज़ जैसे व्यक्ति संवैधानिक पादरी थे जबकि मोहम्मद काज़म यज़्दी जैसे अन्य पादरी संविधानवादी विरोधी माने जाते थे। सफ़ाविद शासन के दौरान शिया सरकार की स्थापना के परिणामस्वरूप इस धार्मिक संप्रदाय के भीतर शक्ति में वृद्धि हुई। पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक सत्ता प्रतिष्ठान में वृद्धि हुई और इसके परिणामस्वरूप बीसवीं शताब्दी में ईरानी समाज के भीतर मूलभूत परिवर्तन हुए, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 1979 में ईरान के शिया इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई।

1979 के बाद की क्रांति: ईरान इस्लामी गणराज्य

ईरानी 1979 की क्रांति के कारण पहलवी राजवंश का तख्तापलट हुआ और ईरान की इस्लामी सरकार की स्थापना हुई । ईरान का शासी निकाय सांप्रदायिकता के स्पष्ट तत्वों को प्रदर्शित करता है जो इसकी प्रणाली की विभिन्न परतों के भीतर दिखाई देते हैं। 1979 की क्रांति के कारण राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आया, जिससे एक नौकरशाही पादरी-शासन की स्थापना हुई जिसने ईरान में शिया संप्रदाय की अपनी व्याख्या बनाई है। [65] जातीय अल्पसंख्यकों और राजनीतिक विरोधियों जैसे अन्य समूहों के प्रति शत्रुता व्यक्त करने के लिए सत्तावादी शासन द्वारा अक्सर धार्मिक भेदभाव का उपयोग किया जाता है। [70] सत्तावादी शासन "हम और वे" प्रतिमान बनाने के लिए धर्म को एक हथियार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इससे सम्मिलित पक्षों के बीच शत्रुता उत्पन्न होती है और यह आंतरिक ही नहीं बाह्य रूप से भी होती है। इसका एक वैध उदाहरण सुन्नियों और बहाइयों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन है । इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना के साथ मध्य-पूर्व में सांप्रदायिक प्रवचन उभरे क्योंकि ईरानी धार्मिक शासन ने इस क्षेत्र में अपने धार्मिक और राजनीतिक विचारों को फैलाने का प्रयास किया और कुछ मामलों में सफल भी हुआ। सांप्रदायिक लेबल वाले ये मुद्दे राजनीतिक रूप से आरोपित हैं। ईरान में सबसे उल्लेखनीय धार्मिक नेताओं को सर्वोच्च-नेताओं का नाम दिया गया है। देश और क्षेत्र में सांप्रदायिकता के विकास में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण साबित हुई है। निम्नलिखित भाग में ईरान के सर्वोच्च-नेतृत्व पर और विस्तार से चर्चा की गई है।

रूहुल्लाह खुमैनी और अली खामेनेई

ईरान-इराक युद्ध के दौरान, ईरान के पहले सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला खुमैनी ने युद्ध में सभी ईरानियों की भागीदारी का आह्वान किया। शिया शहादत के उनके उपयोग से राष्ट्रीय सर्वसम्मति का निर्माण हुआ। [71] 1979 की ईरानी क्रांति के शुरुआती परिणामों में, खुमैनी ने अपने भाषणों में एक सांप्रदायिक स्वर विकसित करना शुरू कर दिया। शियावाद और शिया इस्लाम पर उनका ध्यान बढ़ा

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 3.872| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 4, Issue 9, September 2017 |

जिसे देश की बदलती नीतियों के तहत लागू भी किया गया। खुमैनी ने अपने एक भाषण में कहा: "यरूशलेम का रास्ता कर्बला से होकर गुजरता है।" उनके वाक्यांश की कई अलग-अलग व्याख्याएं हुईं, जिससे क्षेत्र के साथ-साथ देश के भीतर भी उथल-पुथल मच गई। [72] धार्मिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, कर्बला और नजफ , जो दोनों इराक में स्थित हैं, दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में काम करते हैं। इन दोनों शहरों का उल्लेख करके खुमैनी ने शिया विस्तारवाद को जन्म दिया। [73] खुमैनी के इराकी स्नान शासन के साथ युद्ध के कई अंतर्निहित कारण थे और सांप्रदायिकता को मुख्य कारणों में से एक माना जा सकता है। ईरान और इराक के बीच तनाव बेशक केवल संप्रदाय से संबंधित नहीं है, बल्कि धर्म अक्सर ईरानी शासन द्वारा अपने कार्यों को उचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक हथियार है। खुमैनी के शब्द अन्य अरब देशों में भी गूंजे जो इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीनी मुक्ति के लिए लड़ रहे थे। येरुशलम का नाम लेकर खुमैनी ने फ़िलिस्तीन को उसके हाथों से आज़ाद कराने की इच्छा व्यक्त की, जिसे बाद में उन्होंने अक्सर "इस्लाम का दुश्मन" नाम दिया। ईरान ने पूरे क्षेत्र में विद्रोही समूहों का समर्थन किया है। हमास और हिजबुल्लाह के प्रति इसके समर्थन के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई। [74] खुमैनी की मृत्यु के बाद शिया विस्तारवाद की यह इच्छा ख़त्म नहीं हुई। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि तब से इस्लामी गणतंत्र ईरान के भीतर सांप्रदायिक स्वर बढ़ गया है। अली खामेनेई द्वारा तेहरान में आयोजित शुक्रवार की प्रार्थना को शासन के भीतर बढ़ते सांप्रदायिक स्वर के प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। खामेनेई के भाषण बेहद राजनीतिक और सांप्रदायिक हैं. [75] वह अक्सर इजरायल को विश्व मानचित्र से हटाने और शासन का विरोध करने वालों के लिए फतवे जैसी चरम इच्छाओं का उल्लेख करते हैं। [76]

इराक़

सद्दाम हुसैन के पतन के बाद इराक आए सुन्नी इराकी विद्रोह और विदेशी सुन्नी आतंकवादी संगठनों ने सांप्रदायिक हमलों में शिया नागरिकों को निशाना बनाया है। गृह युद्ध के बाद, सुन्नियों ने इराक की शिया बहुसंख्यक सरकारों द्वारा भेदभाव की शिकायत की है, जिसे इस खबर से बल मिला है कि 15 नवंबर 2005 को सरकारी बलों द्वारा इस्तेमाल किए गए परिसर में सुन्नी बंदियों को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया था । [77] यह संप्रदायवाद इसने विशाल स्तर पर उत्प्रवास और आंतरिक विस्थापन को बढ़ावा दिया है।

इराक में सुन्नी अल्पसंख्यकों द्वारा शिया बहुसंख्यकों के उत्पीड़न का एक लंबा इतिहास रहा है। ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद, ब्रिटिश सरकार ने इराकी सिंहासन पर सुन्नी हशमाइट राजशाही को बिठाया , जिसने ईसाई अश्शूरियों और शियाओं द्वारा अपने शासन के खिलाफ विभिन्न विद्रोहों को दबा दिया।

सीरिया

यद्यपि संप्रदायवाद को सीरियाई गृहयुद्ध की विशिष्ट विशेषताओं में से एक के रूप में वर्णित किया गया है , संप्रदायवाद की कथा की उत्पत्ति सीरिया के अतीत में पहले से ही थी।

तुर्क शासन

1850 में अलेप्पो में और उसके बाद 1860 में दमिश्क में जो शत्रुताएँ हुईं , उनके कई कारण थे और वे लंबे समय से चले आ रहे तनाव को दर्शाते थे। हालाँकि, विद्वानों ने दावा किया है कि हिंसा के विस्फोटों को आंशिक रूप से ओटोमन साम्राज्य के भीतर होने वाले आधुनिकीकरण सुधारों, तंज़ीमत के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है , जो 1516 से सीरिया पर शासन कर रहे थे। [78] [79] तंज़ीमत सुधार लाने का प्रयास किया गया ओटोमन साम्राज्य में रहने वाले मुसलमानों और गैर-मुसलमानों के बीच समानता के बारे में । इन सुधारों ने, ओटोमन ईसाइयों की ओर से यूरोपीय हस्तक्षेप के साथ मिलकर, गैर-मुसलमानों को विशेषाधिकार और प्रभाव प्राप्त करने का कारण बना दिया। [80]

रेशम व्यापार व्यवसाय में, यूरोपीय शक्तियों ने स्थानीय संप्रदायों के साथ संबंध बनाए। उन्होंने आम तौर पर एक ऐसे संप्रदाय को चुना जो उनके घरेलू देशों के समान धर्म का पालन करता था, इसलिए वे मुस्लिम नहीं थे। [81] इन विकासों के कारण नए सामाजिक वर्ग उभरे, जिनमें मुख्य रूप से ईसाई, ड्रूज़ और यहूदी शामिल थे। इन सामाजिक वर्गों ने पहले से मौजूद मुस्लिम वर्गों से उनके विशेषाधिकार छीन लिए। एक अन्य विदेशी शक्ति की भागीदारी, हालांकि इस बार गैर-यूरोपीय, का भी सीरिया में सांप्रदायिक संबंधों पर प्रभाव पड़ा। मिस्र के इब्राहिम पाशा ने 1831 और 1840 के बीच सीरिया पर शासन किया। उनकी फूट डालो और राज करो की रणनीति ने मैरोनाइट ईसाइयों को हथियार देकर ड्रूज़ और मैरोनाइट समुदाय के बीच शत्रुता में योगदान दिया। हालाँकि, यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि विभिन्न संप्रदायों ने धार्मिक उद्देश्यों से दूसरों से लड़ाई नहीं की थी, न ही इब्राहिम पाशा का उद्देश्य सांप्रदायिक आधार पर समाज को बाधित करना था। [82] इसे 1840 में इब्राहिम पाशा को हटाने के लिए अपने विद्रोहों में ड्रूज़ और मैरोनाइट्स के एकीकरण द्वारा भी चित्रित किया जा सकता है। यह सांप्रदायिक गठबंधनों और शत्रुता की तरलता और विभिन्न, कभी-कभी गैर-धार्मिक कारणों को दर्शाता है जो सांप्रदायिकता को रेखांकित कर सकते हैं। [9,10]

ऑटोमन शासन के बाद

ओटोमन साम्राज्य के पतन और सीरिया में फ्रांसीसी शासनादेश से पहले , सीरियाई क्षेत्र में पहले से ही मैरोनाइट ईसाइयों, अन्य ईसाइयों, अलावाइट्स , शिया और इस्माइलिया पर नरसंहार देखा गया था , जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न संप्रदायों के सदस्यों के बीच अविश्वास की भावनाएं पैदा हुई थीं। [83] बहुसंख्यक सुन्नी आबादी के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करने के प्रयास

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 3.872| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 4, Issue 9, September 2017 |

में, हेनरी गौरौड की कमान के साथ, फ्रांस ने निम्नलिखित संप्रदायों के लिए पांच राज्य बनाए: अर्मेनियाई , अलावाइट्स, ड्रुज़, मैरोनाइट ईसाई और सुन्नी मुस्लिम। [84] अल्पसंख्यकों पर यह ध्यान नया था और फ्रांसीसियों की फूट डालो और राज करो की रणनीति का हिस्सा था, जिसने संप्रदायों के बीच मतभेदों को बढ़ाया और उनका राजनीतिकरण किया। [79] फ्रांसीसियों द्वारा पुनर्गठन के कारण अलावाइट समुदाय को अपनी हाशिए की स्थिति से आगे बढ़ना पड़ा। इसके अलावा, अलावाइट्स शासक कबीले के परिवार के सदस्यों या अलावाइट समुदाय के अन्य आदिवासी सहयोगियों को शीर्ष स्तर के पद देकर सत्ता की स्थिति प्राप्त करने में भी सक्षम थे। [85]

1961-1980 की अवधि के दौरान, सीरिया पर केवल अलावाइट संप्रदाय का शासन नहीं था, लेकिन सीरिया में बाथ शासन के सुन्नी मुस्लिम चरमपंथी विरोधियों के प्रयासों के कारण, इसे ऐसा माना जाता था। बाथ शासन पर अलावाइट समुदाय के साथ-साथ सत्ता के अन्य संस्थानों का भी वर्चस्व था। [86] इसके परिणामस्वरूप, शासन को सांप्रदायिक माना जाता था, जिसके कारण अलावाइट समुदाय एक साथ इकट्ठा हो गया, क्योंकि उन्हें अपनी स्थिति के लिए डर था। [86] यह अवधि वास्तव में विरोधाभासी है क्योंकि हाफ़िज़ अल-असद ने सीरियाई अरब राष्ट्रवाद बनाने की कोशिश की थी , लेकिन शासन को अभी भी सांप्रदायिक माना जाता था और सांप्रदायिक पहचान को पुन: पेश किया गया और राजनीतिकरण किया गया। [87]

सांप्रदायिक तनाव, जिसने बाद में सीरियाई गृहयुद्ध को जन्म दिया, 1970 से पहले की घटनाओं के कारण समाज में पहले ही प्रकट हो चुका था। उदाहरण के लिए, लेबनान में मैरोनाइट ईसाइयों को राजनीतिक सहायता देकर राष्ट्रपति हाफ़िज़ अल-असद का लेबनानी गृहयुद्ध में शामिल होना । इसे कई सनी मुसलमानों ने देशद्रोह के कृत्य के रूप में देखा, जिसने उन्हें अल-असद के कार्यों को उसकी अलावाइट पहचान से जोड़ दिया। [88] मुस्लिम ब्रदर्स , जो सुन्नी मुसलमानों का एक हिस्सा है, ने अलावियों के प्रति उन तनावों को अपने राजनीतिक एजेंडे और योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। [88] मुस्लिम भाइयों द्वारा कई हत्याएं की गईं, ज्यादातर अलावाइयों के खिलाफ, लेकिन कुछ सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ भी। राष्ट्रपति हाफ़िज़ अल-असद की हत्या का असफल प्रयास यकीनन सबसे प्रसिद्ध है। [89] अलावाइट्स और मुस्लिम ब्रदर्स के सुन्नी इस्लामवादियों के बीच दुश्मनी का एक हिस्सा सीरिया के धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण है , जिसके लिए बाद में अलावाइट्स सत्ता में हैं।

सीरियाई गृहयुद्ध

2015 तक, सीरिया की अधिकांश आबादी में सुन्नी मुसलमान शामिल थे, यानी दो-तिहाई आबादी, जो पूरे देश में पाई जा सकती है। अलावाइट्स दूसरा सबसे बड़ा समूह है, जो आबादी का लगभग 10 प्रतिशत है। [90] यह उन्हें सत्तारूढ़ अल्पसंख्यक बनाता है। अलावी मूल रूप से उत्तर पश्चिमी सीरिया के ऊंचे इलाकों में बसे थे, लेकिन बीसवीं सदी के बाद से लताकिया , होम्स और दमिश्क जैसी जगहों पर फैल गए हैं। [91] सीरिया में पाए जाने वाले अन्य समूह ईसाई हैं, जिनमें मैरोनाइट ईसाई, ड्रुज़ और ट्वेल्वर शिया शामिल हैं। यद्यपि सांप्रदायिक पहचान ने सीरियाई गृहयुद्ध की घटनाओं के सामने आने में भूमिका निभाई, जनजातीय और रिश्तेदारी संबंधों के महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि उनका उपयोग शक्ति और वफादारी प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। [85]

मार्च 2011 में राष्ट्रपति बशर अल-असद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत में , कोई सांप्रदायिक प्रकृति या दृष्टिकोण शामिल नहीं था। विपक्ष के लक्ष्य राष्ट्रीय, समावेशी थे और उसने सामूहिक सीरिया के नाम पर बात की, हालाँकि प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमान थे। [92] विरोध के बाद इसमें बदलाव आया और निम्नलिखित गृह युद्ध को शासन द्वारा सांप्रदायिक संदर्भ में चित्रित किया जाने लगा, जिसके परिणामस्वरूप लोग जातीय आधार पर लामबंद होने लगे। [93] हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि संघर्ष पूरी तरह से या मुख्य रूप से एक सांप्रदायिक संघर्ष है, क्योंकि इसमें सामाजिक-आर्थिक कारक भी शामिल थे। ये सामाजिक-आर्थिक कारक मुख्य रूप से बशर अल-असद के कुप्रबंधित आर्थिक पुनर्गठन का परिणाम थे। [94] इसलिए संघर्ष को अर्ध-सांप्रदायिक के रूप में वर्णित किया गया है, जिससे सांप्रदायिकता गृह युद्ध में एक कारक बन गई है, लेकिन निश्चित रूप से यह युद्ध का कारण बनने में अकेला नहीं है और हर समय और स्थान पर इसका महत्व अलग-अलग है। [95]

स्थानीय ताकतों के अलावा, सामान्य रूप से संघर्ष में बाहरी अभिनेताओं की भूमिका के साथ-साथ संघर्ष के सांप्रदायिक पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि विदेशी शासन पहले फ्री सीरियन आर्मी के समर्थन में थे , लेकिन अंततः उन्होंने धन और हथियारों के साथ सांप्रदायिक मिलिशिया का समर्थन करना शुरू कर दिया। हालाँकि, यह कहना होगा कि उनकी सांप्रदायिक प्रकृति ने न केवल समर्थन के इन प्रवाह को आकर्षित किया, बल्कि उन्होंने इस समर्थन को आकर्षित करने के लिए अधिक सांप्रदायिक और इस्लामी उपस्थिति भी अपनाई। [96]

यमन

यमन में सलाफियों और शिया हाउथिस के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं । द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार , "आज के मध्य पूर्व में, सक्रिय संप्रदायवाद गठबंधन की राजनीतिक लागत को प्रभावित करता है, जिससे सह-धर्मवादियों के बीच यह आसान हो जाता है। इससे यह समझाने में मदद मिलती है कि क्यों सुन्नी-बहुमत राज्य यमन को लेकर ईरान, इराक और हिजबुल्लाह के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं।" [97]

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 3.872| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 4, Issue 9, September 2017 |

ऐतिहासिक रूप से, यमन में धार्मिक आधार पर विभाजन (संप्रदायों) पाकिस्तान, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब और बहरीन की तुलना में कम तीव्र हुआ करते थे। हालाँकि, 2014 में हौथी के अधिग्रहण के बाद स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। [98] [99] [100] [101] यमन में अधिकांश राजनीतिक ताकतें मुख्य रूप से क्षेत्रीय हितों की विशेषता रखती हैं, न कि धार्मिक संप्रदायवाद की। [98] [100] क्षेत्रीय हित, उदाहरण के लिए, उत्तर की हेजाज़ से निकटता, हिंद महासागर व्यापार मार्ग के साथ दक्षिण का तट, और दक्षिणपूर्व के तेल और गैस क्षेत्र हैं। [100] [102] यमन की उत्तरी आबादी में ज़ायदीस का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, और इसकी दक्षिणी आबादी में मुख्य रूप से शफ़ीई लोग शामिल हैं। [100] यमन के दक्षिण-पूर्व में हद्रामौत की एक विशिष्ट सूफी बा'अलावी प्रोफ़ाइल है। [100]

ऑटोमन युग, 1849-1918

1911 की दान संधि के साथ संप्रदायवाद उस क्षेत्र तक पहुंच गया, जिसे कभी अरेबिया फेलिक्स के नाम से जाना जाता था। [103] [104] इसने यमन विलायत को एक ओटोमन नियंत्रित खंड और एक ओटोमन-ज़ायदी नियंत्रित खंड में विभाजित किया। [103] [104] पूर्व में सुन्नी इस्लाम का प्रभुत्व था और बाद में ज़ायदी-शिया इस्लाम का, इस प्रकार यमन विलायत को इस्लामी सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया गया। [103] [104] याह्या मुहम्मद हामिद एड-दीन इस तुर्क इकाई के भीतर जैदी समुदाय का शासक बन गया। [103] [105] समझौते से पहले, यमन विलायत में शफ़ीई और ज़ायदीस के बीच अंतर-सांप्रदायिक लड़ाई कभी नहीं हुई थी। [98] [104] समझौते के बाद भी धार्मिक समुदायों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष सामने नहीं आया। [104] यमनियों के बीच झगड़े प्रकृति में गैर-सांप्रदायिक थे, और ज़ायदीस ने तुर्क अधिकारियों पर इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि वे सुन्नी थे। [104]

ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद, यमन साम्राज्य की स्थापना के साथ शफ़ीई और ज़ायदीस के बीच विभाजन बदल गया। [103] [105] शफ़ीई विद्वानों को याह्या मुहम्मद हामिद एड-दीन के सर्वोच्च अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया, और सेना ने "शफ़ीई लोगों पर ज़ायदी जनजाति के वर्चस्व को संस्थागत बना दिया"। [103] [105]

एकीकरण अवधि, 1918-1990

1990 के यमनी एकीकरण से पहले, यह क्षेत्र कभी भी एक देश के रूप में एकजुट नहीं हुआ था। [98] [106] एकता बनाने और सांप्रदायिकता पर काबू पाने के लिए, काहतनाइट के मिथक को एक राष्ट्रवादी कथा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। [100] हालांकि यमन के सभी जातीय समूह इस कथा में फिट नहीं बैठते, जैसे अल-अखदम और तेमानिम। [100] [107] बाद वाले ने प्राचीन यमन में एक यहूदी साम्राज्य की स्थापना की, जो फ़िलिस्तीन के बाहर बनाया गया एकमात्र राज्य था। [108] यहूदी राजा धू नुवास द्वारा अंजाम दिए गए ईसाइयों के नरसंहार के कारण अंततः होमेराइट साम्राज्य का पतन हो गया। [103] [108] आधुनिक समय में, यहूदी राज्य की स्थापना के परिणामस्वरूप 1947 के अदन दंगे हुए, जिसके बाद ऑपरेशन मैजिक कार्पेट के दौरान अधिकांश तीमानिम ने देश छोड़ दिया। [107]

उत्तरी यमन गृहयुद्ध (1962-1970) के दौरान परस्पर विरोधी भूराजनीतिक हित सामने आये। [106] वहाबवादी सऊदी अरब और अन्य अरब राजतंत्रों ने यमन साम्राज्य के अपदस्थ ज़ायदी इमाम मुहम्मद अल-बद्र का समर्थन किया। [98] [106] [109] उनके प्रतिद्वंद्वी, अब्दुल्ला अल-सल्लल को मिस्र और अन्य अरब गणराज्यों से समर्थन मिला। [98] [106] [109] दोनों अंतरराष्ट्रीय समर्थन धार्मिक सांप्रदायिक संबद्धता पर आधारित नहीं थे। [98] [106] [109] [110] हालांकि, यमन में राष्ट्रपति अब्दुल्ला अल-सल्लल (एक ज़ायदी) ने अपने उपराष्ट्रपति अब्दुर्रहमान अल-बैदानी (एक शफ़ीई) को ज़ायदी संप्रदाय का सदस्य नहीं होने के कारण दरकिनार कर दिया। [103] [108] उत्तरी यमन के शफ़ीई अधिकारियों ने भी इस अवधि में "निचले यमन में एक अलग शफ़ीई राज्य की स्थापना" की पैरवी की। [103]

समकालीन सुन्नी-शिया प्रतिद्वंद्विता

लिसा वेडेन के अनुसार, मुस्लिम दुनिया में सुन्नियों और शियाओं के बीच कथित सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता यमन की सलाफिस्टों और हौथिस के बीच सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता के समान नहीं है। [109] हौथी के अंसार अल्लाह आंदोलन के सभी समर्थक शिया नहीं हैं, और सभी ज़ायदी हौथी नहीं हैं। [100] [111] [110] हालांकि अधिकांश हौथिस शिया की ज़ायदी शाखा के अनुयायी हैं, दुनिया में अधिकांश शिया ट्वेल्वर शाखा से हैं। यमन भौगोलिक रूप से तथाकथित शिया क्रिसेंट के निकट नहीं है। हिज़्बुल्लाह और ईरान को, जिनके विषय ज़्यादातर बारह शिया हैं, हौथिस के साथ जोड़ने के लिए राजनीतिक उद्देश्यों के लिए शोषण किया जाता है। [105] [111] [110] [112] [113] सऊदी अरब ने ऑपरेशन स्कोच्ड अर्थ के दौरान हौथियों के लिए ईरान के कथित सैन्य समर्थन पर जोर दिया। [98] [111] [114] हौथी आंदोलन का नारा है 'अमेरिका को मौत, इसराइल को मौत, यहूदियों को अभिशाप'। यह ईरान और हिजबुल्लाह का एक रूप है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि हौथियों को उनके साथ कथित जुड़ाव के बारे में कोई परेशानी नहीं है। [100] [105] [111] [114]

जनजातियाँ और राजनीतिक आंदोलन [10]

पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन की नीतियों के कारण दक्षिणी क्षेत्रों में जनजातीय संस्कृति वस्तुतः गायब हो गई है। [100] [115] हालाँकि, यमन का उत्तरी भाग अभी भी बकील और हाशिद के शक्तिशाली आदिवासी संघों का घर है। [100] ये आदिवासी

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 3.872| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 4, Issue 9, September 2017 |

संघ राज्य के हस्तक्षेप के बिना जेलों , अदालतों और सशस्त्र बलों जैसे अपने स्वयं के संस्थानों को बनाए रखते हैं । [100] बकील के विपरीत, हाशिदों ने सलाफिस्ट सिद्धांतों को अपनाया, और सादा युद्ध (2004-2015) के दौरान सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। [100] यमन के सलाफ़िस्टों ने सादाह में रज़ीह की ज़ायदी मस्जिद पर हमला किया और पूरे यमन में ज़ायदी इमामों की कब्रों को नष्ट कर दिया। [99] [100] [109] बदले में, हौथियों ने दम्मज की घेराबंदी के दौरान यमन के मुख्य सलाफिस्ट केंद्र मुक़बिल बिन हादी अल-वादी पर हमला किया । [99] [100] [110] हौथियों ने सलाफिस्ट बिन सलमान मस्जिद पर भी हमला किया और विभिन्न तेमानिम परिवारों को धमकी दी। [105] [114]

हाशिद के अभिजात वर्ग के सदस्यों ने सुन्नी इस्लामवादी पार्टी अल-इस्लाह की स्थापना की और, एक समकक्ष के रूप में, हिज़्ब अल-हक़ की स्थापना बकील के अभिजात वर्ग के समर्थन से ज़ायदिस द्वारा की गई थी। [100] [110] [114] हिंसक गैर-राज्य अभिनेता अल-कायदा, अंसार अल-शरिया और दाएश , जो विशेष रूप से मुकल्ला जैसे दक्षिणी शहरों में सक्रिय हैं , यमन के इस्माइलिस , ज़ायदीस और अन्य के प्रति अपनी दुश्मनी के साथ सांप्रदायिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। [98] [100] [116] [117] [118] 1995 में यमन के इस्लामवादियों द्वारा किए गए होस्नी मुबारक की हत्या के प्रयास ने देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। [105] आतंक के विरुद्ध युद्ध ने यमन की राजनीति पर सलाफिस्ट-जिहादी समूहों के प्रभाव को और मजबूत कर दिया । [100] [105] [109] 2000 यूएसएस कोल बमबारी के परिणामस्वरूप यमन की धरती पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई हुई। [100] [105] संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैनात क्रूज मिसाइलों , क्लस्टर बमों और ड्रोन हमलों के कारण होने वाली संपार्श्विक क्षति ने यमन की संप्रभुता से समझौता किया । [100] [105] [110]

अली अब्दुल्ला सालेह का शासनकाल

अली अब्दुल्ला सालेह हाशिद के सनहान कबीले से एक ज़ायदी हैं और राष्ट्रवादी पार्टी जनरल पीपुल्स कांग्रेस के संस्थापक हैं । [100] राज्य के प्रमुख के रूप में अपने दशकों लंबे शासनकाल के दौरान , उन्होंने ज़ायदी की इस्लामी पुनरुद्धार वकालत के खिलाफ सादाह के सलाफिस्ट के वैचारिक प्रसार का इस्तेमाल किया । [109] [114] इसके अलावा, यमन के सशस्त्र बलों ने हौथिस के खिलाफ लड़ने के लिए सलाफिस्टों को भाड़े के सैनिकों के रूप में इस्तेमाल किया । [100] हालाँकि, अली अब्दुल्ला सालेह ने यमन के मुस्लिम ब्रदरहुड के राजनीतिक प्रतिकार के रूप में भी हौथिस का इस्तेमाल किया । [105] [114] हौथिस द्वारा केंद्र सरकार के लगातार विरोध के कारण, ऊपरी यमन राज्य द्वारा आर्थिक रूप से हाशिए पर था। [105] [114] अली अब्दुल्ला सालेह द्वारा क्रियान्वित फूट डालो और राज करो की इस नीति ने यमन की सामाजिक एकता को खराब कर दिया और यमन के समाज के भीतर सांप्रदायिक धारणाओं को बढ़ावा दिया। [105] [109] [114]

अरब स्प्रिंग और यमनी क्रांति के बाद , अली अब्दुल्ला सालेह को 2012 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। [100] [119] इसके बाद, तीन राष्ट्रीय गठबंधनों के बीच एक जटिल और हिंसक सत्ता संघर्ष छिड़ गया : (1) अली अब्दुल्ला सालेह, उनकी राजनीतिक पार्टी जनरल पीपुल्स कांग्रेस, और हौथिस; (2) अली मोहसिन अल-अहमर , राजनीतिक दल अल-इस्लाह द्वारा समर्थित; (3) अब्दरब्बुह मंसूर हादी , संयुक्त बैठक दलों द्वारा समर्थित। [110] [112] [120] इब्राहिम फ़्रैहत के अनुसार, "यमन का संघर्ष कभी भी सांप्रदायिकता के बारे में नहीं रहा है, क्योंकि हौथिस मूल रूप से आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों से प्रेरित थे। हालाँकि, 2014 में, क्षेत्रीय संदर्भ काफी हद तक बदल गया। [112] 2014-2015 में हौथी अधिग्रहण ने सऊदी के नेतृत्व वाले हस्तक्षेप को उकसाया , जिससे संघर्ष के सांप्रदायिक आयाम को मजबूत किया गया। [98] [112] हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह ने सऊदी हस्तक्षेप की भारी आलोचना की, इसके पीछे क्षेत्रीय सुन्नी-शिया भूराजनीतिक गतिशीलता को बल दिया। [112]

सऊदी अरब

सऊदी अरब में सांप्रदायिकता का उदाहरण इसकी शिया आबादी के साथ तनाव है, जो सऊदी आबादी का 15% तक है। [121] इसमें सऊदी सरकार द्वारा शिया विरोधी नीतियां और शियाओं का उत्पीड़न शामिल है। [122] ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार , शियाओं को शिक्षा और कार्यस्थल में भेदभाव का सामना करते हुए सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानूनी और आर्थिक रूप से हाशिए का सामना करना पड़ता है। [123] यह इतिहास 1744 का है, जब हाउस ऑफ सऊद और वहाबियों के बीच गठबंधन की स्थापना हुई थी , जो शियावाद को बहुदेववाद के बराबर मानते थे। [124] बीसवीं सदी के दौरान शियाओं और सऊदी शासन के बीच झड़पें और तनाव सामने आए, जिनमें 1979 कातिफ विद्रोह और 1987 मक्का घटना के नतीजे शामिल थे । [124] [125] हालांकि 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में संबंधों में तनाव आया, 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक में हुए चुनाव (क्षेत्र में शियावाद के व्यापक उदय के कारण) के बाद तनाव फिर से बढ़ गया और अरब के दौरान चरम पर पहुंच गया। वसंत । [121] सऊदी अरब में सांप्रदायिकता ने ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित मानवाधिकार समूहों का व्यापक ध्यान आकर्षित किया है, खासकर 2016 में शिया मौलवी निम्र अल-निम्र की फांसी के बाद, जो 2011 के घरेलू विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय थे । [126] क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सुधारों के बावजूद , शियाओं को आज भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। [127] [128]

लेबनान

लेबनान में सांप्रदायिकता को राज्य और गैर-राज्य संस्थानों के भीतर औपचारिक और वैध बना दिया गया है और इसे इसके संविधान में अंकित किया गया है। लेबनान 18 विभिन्न संप्रदायों को मान्यता देता है, मुख्यतः मुस्लिम और ईसाई दुनिया के भीतर। लेबनान में संप्रदायवाद की नींव 19वीं सदी के मध्य में ओटोमन शासन के दौरान पड़ी। इसके बाद 1920 में लेबनान गणराज्य के निर्माण और

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 3.872| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 4, Issue 9, September 2017 |

1926 के संविधान और 1943 के राष्ट्रीय समझौते के साथ इसे सुदृढ़ किया गया। 1990 में, ताइफ़ समझौते के साथ, संविधान को संशोधित किया गया लेकिन राजनीतिक संप्रदायवाद से संबंधित पहलुओं में संरचनात्मक रूप से बदलाव नहीं किया गया। [129] लेबनान में सांप्रदायिकता की गतिशील प्रकृति ने कुछ इतिहासकारों और लेखकों को इसे " सर्वोत्कृष्ट सांप्रदायिक राज्य " के रूप में संदर्भित करने के लिए प्रेरित किया है क्योंकि यह एक संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था के साथ धार्मिक समुदायों और उनके असंख्य उप-विभाजनों का मिश्रण है। मिलान। [130] फिर भी, ज़मीनी हकीकत इस तरह के निष्कर्ष से कहीं अधिक जटिल रही है, क्योंकि जैसा कि नाद्या सबैती ने अपने शोध में दिखाया है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, "सामूहिक भविष्य को आकार देने की ज़रूरत है जो बदलती अवधारणाओं के समानांतर हो" नव प्रादेशिक राष्ट्र-राज्य लेबनान का" [18] स्पष्ट रूप से मौजूद था। “जनादेश के दौरान, शैक्षिक अभ्यासकर्ताओं और स्कूलों की विस्तृत श्रृंखला ने इस इकाई को बनाने के मार्ग में ज्ञानमीमांसीय बुनियादी ढांचे को आकार देने में मदद की। 'ज्ञानमीमांसीय बुनियादी ढाँचे' से तात्पर्य उन विचारों की विस्तृत श्रृंखला से है जो सत्य और ठोस स्पष्टीकरण के रूप में मान्य हो जाते हैं।" [131] दूसरे शब्दों में, औपनिवेशिक सांप्रदायिक शिक्षा प्रणाली के विपरीत, "छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने पाठ्यक्रम और शैक्षिक प्रथाओं के माध्यम से शैक्षिक सामग्री बनाई ताकि नए 'ज्ञान के समुदाय' का निर्माण किया जा सके। ज्ञान के ये समुदाय, विचारों की दुनिया और ज्ञान के नेटवर्क से जुड़े हुए थे, अक्सर इकबालिया, सामाजिक-राजनीतिक और यहां तक कि कभी-कभी क्षेत्रीय विषय-वस्तुओं से भी आगे निकल जाते थे। [131]

विचार-विमर्श

भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसम्बर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो भागों - भारत और पाकिस्तान में बँट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सो में बँट गई - भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा।

भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन कि याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन का समय लगा था।

संक्षिप्त परिचय

भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्द्रीय संसद की परिषद् में राष्ट्रपति तथा दो सदन है जिन्हें राज्यों की पर प्रधानमन्त्री होगा, राष्ट्रपति इस मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मन्त्रिपरिषद में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।[8] मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आन्ध्रप्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मन्त्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमन्त्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मन्त्रिपरिषद से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।

संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत तीन सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्य क्षेत्र कहा जाता है।

भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषताएँ भी हैं[9]

- 1. यह संघ राज्यों के परस्पर समझौते से नहीं बना है
- 2. राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते है, केवल एक ही संविधान केन्द्र तथा राज्य दोनो पर लागू होता है
- 3. भारत में द्वैध नागरिकता नहीं है। केवल भारतीय नागरिकता है
- 4. भारतीय संविधान में आपातकाल लागू करने के उपबन्ध है [352 अनुच्छेद] के लागू होने पर राज्य-केन्द्र शक्ति पृथक्करण समाप्त हो जायेगा तथा वह एकात्मक संविधान बन जायेगा। इस स्थिति में केन्द्र-राज्यों पर पूर्ण सम्प्रभु हो जाता है
- 5. राज्यों का नाम, क्षेत्र तथा सीमा केन्द्र कभी भी परिवर्तित कर सकता है [बिना राज्यों की सहमति से] [अनुच्छेद 3] अत: राज्य भारतीय संघ के अनिवार्य घटक नहीं हैं। केन्द्र संघ को पुर्ननिर्मित कर सकती है

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 3.872| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 4, Issue 9, September 2017 |

- 6. संविधान की 7वीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं [संघीय सरकार|संघीय], [राज्य सूची|राज्य], तथा [समवर्ती सूची|समवर्ती]। इनके विषयों का वितरण केन्द्र के पक्ष में है।

    - 6.1 संघीय सूची में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हैं
    - 6.2 इस सूची पर केवल संसद का अधिकार है
    - 6.3 राज्य सूची के विषय कम महत्वपूर्ण हैं, 5 विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद विधि निर्माण कर सकती है किंतु किसी एक भी परिस्थिति में राज्य, केन्द्र हेतु विधि निर्माण नहीं कर सकते-

    - क1. अनु 249—राज्य सभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित हेतु यह आवश्यक है [2/3 बहुमत से] किंतु यह बन्धन मात्र 1 वर्ष हेतु लागू होता है
    - क2. अनु 250— राष्ट्र आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार स्वत: मिल जाता है
    - क3. अनु 252—दो या अधिक राज्यों की विधायिका प्रस्ताव पास कर राज्य सभा को यह अधिकार दे सकती है [केवल संबंधित राज्यों पर]
    - क4. अनु 253--- अंतराष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के लिए संसद राज्य सूची विषय पर विधि निर्माण कर सकती है
    - क5. अनु 356—जब किसी राज्य में [राष्ट्रपति शासन] लागू होता है, उस स्थिति में संसद उस राज्य हेतु विधि निर्माण कर सकती है

- 7. अनुच्छेद 155 – राज्यपालों की नियुक्ति पूर्णत: केन्द्र की इच्छा से होती है इस प्रकार केन्द्र राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है
- 8. अनु 360 – वित्तीय आपातकाल की दशा में राज्यों के वित्त पर भी केन्द्र का नियंत्रण हो जाता है। इस दशा में केन्द्र राज्यों को धन व्यय करने हेतु निर्देश दे सकता है
- 9. प्रशासनिक निर्देश [अनु 256-257] -केन्द्र राज्यों को राज्यों की संचार व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाये, के बारे में निर्देश दे सकता है, ये निर्देश किसी भी समय दिये जा सकते है, राज्य इनका पालन करने हेतु बाध्य है। यदि राज्य इन निर्देशों का पालन न करे तो राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होने का अनुमान लगाया जा सकता है
- 10. अनु 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है ये सेवक नियुक्ति, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक क्षेत्रों में पूर्णतः: केन्द्र के अधीन है जबकि ये सेवा राज्यों में देते है राज्य सरकारों का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है
- 11. एकीकृत न्यायपालिका
- 12. राज्यों की कार्यपालिक शक्तियाँ संघीय कार्यपालिक शक्तियों पर प्रभावी नहीं हो सकती है।

परिणाम

समकालीन राजनीतिक दर्शन को पिछले ग्यारह वर्षों में एंग्लो-अमेरिकी राजनीतिक दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण विकासों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है, विशेष रूप से राजनीतिक उदारवाद, विचारशील लोकतंत्र, नागरिक गणतंत्रवाद, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक बहुलवाद पर नई बहस। पाठ में अब उपयोगितावाद, उदार समतावाद, स्वतंत्रतावाद, समाजवाद, समुदायवाद और नारीवाद पर अद्यतन अध्यायों के अलावा, नागरिकता सिद्धांत और बहुसंस्कृतिवाद पर दो नए अध्याय शामिल हैं। जिन विचारकों पर चर्चा की गई उनमें जीए कोहेन, रोनाल्ड ड्वॉर्किन, विलियम गैलस्टन, कैरोल गिलिगन, आरएम हेयर, कैथरीन मैकिनॉन, डेविड मिलर, फिलिप वान पारिज, सुसान ओकिन, रॉबर्ट नोज़िक, जॉन रॉल्स, जॉन रोमर, माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर, माइकल वाल्ज़र शामिल हैं। , और आइरिस यंग। पद छोड़ने के बाद राजनेताओं को एक महत्वपूर्ण विरासत मिलती है: कार्यालय में अपने समय की जनता की यादें। दरअसल, मीडिया अक्सर राजनेताओं की प्रमुख प्रेरणा के रूप में विरासत संबंधी चिंताओं पर चर्चा करता है। फिर भी, राजनेताओं की विरासतों की व्यापक जनता द्वारा व्याख्या और उपयोग कैसे की जाती है, इसका अनुभवजन्य विश्लेषण बहुत कम हुआ है। ऑनलाइन चर्चा मंचों से लाखों टिप्पणियों का विश्लेषण करते हुए, हम दिखाते हैं कि नागरिक वर्तमान घटनाओं की चर्चा में अक्सर अतीत के राजनेताओं की यादें जुटाते हैं। [8,9]

निष्कर्ष

एक यादृच्छिक सर्वेक्षण प्रयोग पिछले राजनेताओं के ऐसे आह्वान को तर्कसंगत बनाता है: वे समकालीन तर्कों की प्रेरकता को बढ़ाते हैं - विशेष रूप से बुरे तर्क - लेकिन केवल जब किसी नीति डोमेन के संदर्भ में विशेष रूप से पिछले राजनेता से जुड़े होते हैं। हमारे

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 3.872| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 4, Issue 9, September 2017 |

निष्कर्षों से पता चलता है कि राजनेताओं को एक सकारात्मक, व्यापक और स्थायी विरासत विकसित करने में गहरी रुचि है क्योंकि उनकी यादें कार्यालय छोड़ने के बाद लंबे समय तक नीतिगत बहस को प्रभावित करती हैं।[10]

संदर्भ

1. "Preface, The constitution of India" (PDF). http://india.gov.in/my-government/constitution-india/constitution-india-full-text. Government of India. मूल से 31 मार्च 2015 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 5 February 2015. ।
2. ↑ "Introduction to Constitution of India". Ministry of Law and Justice of India. 29 July 2008. मूल से 22 अक्तूबर 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2008-10-14.
3. ↑ Das, Hari (2002). Political System of India. Anmol Publications. पृ॰ 120. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-7488-690-7.
4. ↑ "The Constitution of India: Role of Dr. B.R. Ambedkar". मूल से 2 April 2015 को पुरालेखित.
5. ↑ "http://www.inbais.com/2016/02/article-1-to-395-in-hindi.html". मूल से 24 जून 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 जून 2016. ।
6. ↑ [https://www.drishtiias.com/gs-special/gs-special-polity/important-sources-of-the-indian-constitution]
7. ↑ Pylee, M.V. (1997). India's Constitution. S. Chand & Co. पृ॰ 3. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-219-0403-X.
8. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 11 मई 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2016.
9. ↑ "भारत का संविधान (पूर्ण पाठ)". मूल से 25 दिसंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2016.
10. ↑ "दूसरी अनुसूची" (PDF). मूल (PDF) से 18 जनवरी 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 फरवरी 2016.